पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 5058/2024

==========

मन्नू कुमार संजय कुमार का बेटा, मोहल्ला-अशोक विहार कॉलोनी का निवासी, किड्ज़ी स्कूल के पास, उर्मिला ब्यूटी पार्लर के सामने, गया बाईपास, थाना- विष्णुपद, जिला-गया।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने अध्यक्ष के माध्यम से।
3. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिती:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री ऋषि राज रमन, अधिवक्ता
		सुश्री रुचि मंडल, अधिवक्ता
		श्री कुणाल, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री धुर्जती कुमार प्रसाद, जी. पी.-14
बी. पी. एस. सी. के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता
		श्री के. शंकर, अधिवक्ता

श्री रजनी कांत झा, अधिवक्ता

श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

श्रीमती पी. साहिल, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *बिहार औषधि नियंत्रक संवर्ग विनियमन, 2014 की धारा 5(1)*
- *औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 49, 49 ए*
- *फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10*
- *फार्म डी विनियमन, 2008*
- *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3)*

संदर्भित मामले:

- *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नमित शर्मा, (2013) 10 एससीसी 359 में रिपोर्ट किया गया*
- *यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम प्राइजर लिमिटेड एवं अन्य, 2018 (2) एससीसी 39 में रिपोर्ट किया गया*
- *प्रोफेसर यशपाल एवं अन्य। बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, (2005) 5 एससीसी 420 में रिपोर्ट किया गया*
- *फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ. एस. के. तोषनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट्स, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं अन्य, (2021) 10 एससीसी 657 में रिपोर्ट किया गया*
- *कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2022) 11 एससीसी 392 में रिपोर्ट किया गया*

• सत्येंद्र सिंह एवं अन्य बनाम संजय कुमार एवं अन्य, 2001 (1) पीएलजेआर 104 में रिपोर्ट किया गया

• महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वराडे एवं अन्य और इसके अनुरूप मामले, 2019 (6) एससीसी 362 में रिपोर्ट किया गया

• पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य, (2021) 16 एससीसी 340 में रिपोर्ट किया गया

• मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम अनित कुमार दास, (2021) 12 एससीसी 80 में रिपोर्ट किया गया

• योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एनसीटी, दिल्ली सरकार एवं अन्य, (2003) 3 एससीसी 548 में रिपोर्ट किया गया

***रिट याचिका** - बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए विज्ञापन के अनुसार अर्हता नहीं रखने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया।*

याचिकाकर्ता को फार्मेसी में डॉक्टर की डिग्री (Pharm D) प्रदान की गई थी। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन किया, जिसके लिए योग्यता बी. फार्म (B. Pharm) डिग्री निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके पास Pharm D डिग्री थी।

***निर्णय** - ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता "डिग्री" होना है, न कि "डॉक्टरेट डिग्री"। अतः, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक योग्यता केवल फार्मेसी में स्नातक डिग्री तक सीमित नहीं है, गलत है और इसे खारिज किया जाना उपयुक्त है। (पैरा 21)*

यह निष्कर्ष निकालना कि उच्च योग्यता अनिवार्य रूप से किसी अन्य, यद्यपि निम्न, योग्यता की उपलब्धि को पूर्वनिर्धारित करती है, तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि इस प्रभाव से संबंधित कोई नियम मौजूद न हो। किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण भर्ती नीति का विषय है और नियोक्ता के रूप में राज्य को योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। अतः, निर्धारित योग्यता के दायरे को बढ़ाना न्यायिक समीक्षा का कार्य या भूमिका नहीं है। (पैरा 23)

सार्वजनिक सेवा में भर्ती विज्ञापन और भर्ती नियमों के अनुसार सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि नियमों से विचलन अयोग्य व्यक्तियों को प्रवेश का अवसर देता है और उन कई अन्य व्यक्तियों को वंचित करता है जो पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। (पैरा 24)

रिट याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 26)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

सी. ए. वी. जजमेंट

तारीखः 20.07.2024

वर्तमान रिट याचिका परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे इसके बाद "प्रतिवादी-आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण नोटिस दिनांक 13.03.2024 को रद्द करने के लिए दायर की गई है जो औषधि निरीक्षक प्रतिस्पर्धा परीक्षा (2022 का विज्ञापन सं. 09) के संबंध में था,

जिसके तहत याचिकाकर्ता को विज्ञापन के अनुसार योग्यता नहीं रखने के आधार पर औषधि निरीक्षक के पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और अयोग्यता के मुद्दे पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी घोषणा करने का अनुरोध किया है कि बिहार औषधि नियंत्रक संवर्ग विनियम, 2014 (इसके बाद "संवर्ग विनियम, 2014" के रूप में संदर्भित) के खंड 5 (1) के संदर्भ में औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता वही है जो औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 (इसके बाद "नियम, 1945" के रूप में संदर्भित) के नियम 49 में प्रदान की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति होगा, जिसके पास नैदानिक फार्माकोलॉजी या माइक्रोबाइलोजी में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री है। कानून द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के साथ- साथ यह भी कि प्रत्यर्थी अधिकारी भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 के संदर्भ में याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार करने के लिए बाध्य है, जो यह निर्धारित करता है कि फार्म डी योग्यता रखने वाला व्यक्ति स्वत: विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा, जहां फार्मेसी में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी कि योगयता रखने वाला व्यक्ति नियुक्त होने के योग्य है। अंत में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-आयोग दिनांक 05.04.2024 के निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया है जिसके तहत यह बताया गया है कि तीन सदस्यीय विभागीय विशेषज्ञ समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति की जांच की, जिसके बाद उसने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अयोग्य पाया।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने विज्ञान के साथ +2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय,

मुरादाबाद में फार्म डी (डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और उक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 12.09.2022 पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री से सम्मानित किया गया। प्रतिवादी-आयोग ने औषधि निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए 2022 का विज्ञापन सं. 09 दिनांक 22.11.2022 का एक विज्ञापन प्रकाशित किया और उसके खंड 3 में शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है:-

> *"एक व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा, वह एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय" से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री हो।"*
>
> भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।"

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया कि प्रतिवादी-आयोग ने नियम, 1945 के नियम 49 में उल्लिखित "फार्मेसी में डिग्री" शब्द की व्याख्या फार्मेसी में केवल स्नातक की डिग्री के रूप में की है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार, जिन्होंने बी. फार्म की योग्यता प्राप्त किए बिना सीधे फार्म डी की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 2022 के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 09 के खिलाफ आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

3. यह बताया गया है कि इस बीच, रोनित कुमार अरविंद नामक व्यक्ति ने 2023 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4751 वाली एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कमोबेश एक ही मुद्दा शामिल था और इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी-आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह 29.05.2023 द्वारा दायर किए जाने की स्थिति में अपने आवेदन पत्र को अस्थायी रूप से स्वीकार करे। इसके बाद, प्रत्यर्थी-आयोग ने दिनांक 23.05.2023 पर एक

महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया था, जिसमें 2023 की सीडब्ल्यूजेसी सं. 4751 वाली उक्त रिट याचिका के परिणाम के अधीन, औषधि निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने के लिए फार्म डी की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने अनारक्षित श्रेणी में औषधि निरीक्षक के पद के लिए भी आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें अनुक्रमांक 901580 आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता तब 07.07.2023 से 10.07.2023 तक आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ था, जिसका परिणाम 23.01.2024 को घोषित किया गया। प्रतिवादी-आयोग ने तब, दिनांक 31.01.2024 के महत्वपूर्ण नोटिस के माध्यम से, उम्मीदवारों को 01.02.2024 से 07.02.2024 दस्तावेज़ अपलोड करने और 12.02.2024 और 13.02.2024 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आने का निर्देश दिया। जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, उसे 12.02.2024 पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आने के लिए कहा गया था और वास्तव में, वह दी गई तारीख को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए भी उपस्थित हुआ था। चूंकि उपरोक्त रोहित कुमार अरविंद ने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उन्होंने 07.03.2024 पर उपरोक्त रिट याचिका वापस ले ली, जिसके बाद, प्रतिवादी-आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने विवादित महत्वपूर्ण नोटिस दिनांक 13.03.2024, सूचित किया कि याचिकाकर्ता विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं करता है, इसलिए उसे "अयोग्य उम्मीदवार" की श्रेणी में रखा गया है। फिर भी, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-आयोग के ईमेल आईडी पर अपनी अयोग्यता के मुद्दे पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए 19.03.2024 तक का समय दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तब 15.03.2024 को ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता इस अदालत के समक्ष आया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रशांत सिन्हा ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 10.05.2008 को तैयार किए गए फार्म डी विनियम, 2008 (जिसे आगे "विनियम, 2008" कहा जाएगा) का हवाला दिया है। विनियम 2008 के विनियम 3 में, पाठ्यक्रम की अवधि का प्रावधान है और जहां तक फार्म-डी पाठ्यक्रम का संबंध है, पाठ्यक्रम की अवधि छह शैक्षणिक वर्ष (अध्ययन के पांच वर्ष और इंटर्नशिप या निवास के एक वर्ष) पूर्णकालिक निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवसों की अवधि में फैला हुआ है, जबकि फार्म-डी (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम की अवधि 3 शैक्षणिक वर्ष (अध्ययन के दो वर्ष और इंटर्नशिप या निवास के एक वर्ष) पूर्णकालिक के रूप में निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवसों की अवधि में फैला हुआ है। फार्मेसी डी भाग-1 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता, फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से गणित या जीव विज्ञान के साथ अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में 10+2 के साथ उत्तीर्ण होना है। फार्म डी (स्नातकोत्तर) में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से बी. फार्म में उत्तीर्ण है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग विनियमन, 2014 (जिसे आगे "संवर्ग विनियमन, 2014" कहा जाएगा) का भी हवाला दिया है, जिसे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचना दिनांक 8.10.2014 के तहत तैयार किया है। संवर्ग विनियमन, 2014 के विनियमन 2(12) में "औषधि निरीक्षक" को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार औषधि नियंत्रक

संवर्ग के मूल संवर्ग पद पर नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। विनियमन, 2014 का विनियम 5 नियम, 1945 के नियम 49 के अनुसार औषधि निरीक्षक के मूल संवर्ग पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। नियम, 1945 के नियम 49 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

> ***"49. निरीक्षकों की योग्यताएँ -*** *एक व्यक्ति जो अधिनियम के तहत नियुक्त एक निरीक्षक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कानून द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री है:*
>
> *बशर्ते कि केवल वे निरीक्षकः-*
>
> > *(i) जिनके पास अनुसूची सी में निर्दिष्ट पदार्थों में से कम से कम एक के निर्माण में 18 महीने से कम का अनुभव नहीं है. या*
> >
> > *(ii)* जिनके पास लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला में अनुसूची सी में कम से कम एक पदार्थ के परीक्षण में 18 महीने से कम का अनुभव नहीं है, या
> >
> > *(iii) जिन्होंने औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान अनुसूची सी में निर्दिष्ट किसी भी पदार्थ का निर्माण करने वाली फर्मों के निरीक्षण में कम से कम तीन साल का अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें अनुसूची सी में उल्लिखित पदार्थों के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।*
> >
> > *[बशर्ते कि शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता 18 अक्टूबर, 1993 को या उससे पहले निरीक्षकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।"*

6. वास्तव में, नियम, 1945 के नियम 49 ए को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए भी संदर्भित किया गया है कि एक लाइसेंस प्राधिकरण की योग्यता है *भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक*, इसका अर्थ यह है कि नियम 49 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निरीक्षक के लिए निर्धारित योग्यता फार्मेसी में स्नातक/स्नातक की डिग्री है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता केवल फार्मेसी में स्नातक की डिग्री तक सीमित नहीं है, इसलिए उत्तरदाताओं की व्याख्या है कि अभिव्यक्ति "फार्मेसी में डिग्री", योग्यता को केवल स्नातक डिग्री या स्नातक डिग्री तक सीमित करती है, जो उत्तरदाताओं द्वारा "फार्मेसी में डिग्री" अभिव्यक्ति से पहले स्नातक या स्नातक राशि को जोड़ने के लिए है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शब्दों को जोड़ने या घटाने से बचा जाना चाहिए। इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भारत संघ बनाम नमित शर्मा*** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2013) 10 एससीसी 359*** में दी गई है, पैरा संख्या 32 और 33 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> ***"32.*** *इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 (5) और 15 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, साथ ही ऐसी कोई बुनियादी योग्यता भी*

निर्धारित नहीं की गई है जो ऐसे व्यक्तियों के पास संबंधित क्षेत्रों में होनी चाहिए जिसमें वे काम करते हैं। हालाँकि, समीक्षाधीन निर्णय में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 (5) और 15 (5) को "पढ़ा" है और कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के पास संबंधित क्षेत्र में बुनियादी डिग्री होनी चाहिए क्योंकि अन्यथा अधिनियम की धारा 12 (5) और 15 (5) समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए बाध्य हैं। यह धारा 12 (5) और 15 (5) के प्रावधानों का "अध्ययन" है। अधिनियम के जिन शब्दों का संसद ने इरादा नहीं किया है, वे इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

33. *भारत संघ बनाम देउकी नंदन अग्रवाल [1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 323] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय क़ानून की भाषा में किसी भी कमी या चूक को ठीक या पूरा नहीं कर सकता है। वी. रामास्वामी, न्यायधीश तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निर्णय लिखते हुए कहते हैंः (एस. सी. सी. पी. 332, पैरा 14)*

> *"14. ... यह अदालत का कर्तव्य नहीं है कि वह कानून के दायरे को बढ़ाए या विधायिका के इरादे को बढ़ाए, जब प्रावधान की भाषा सीधा और स्पष्ट हो। अदालत इस अच्छे कारण से कानून को फिर से नहीं लिख सकती, फिर से तैयार नहीं कर सकती या फिर से तैयार नहीं कर सकती कि उसके पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। कानून बनाने की शक्ति अदालतों को नहीं दी गई है। न्यायालय किसी कानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता है या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता है जो वहां नहीं हैं। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक है, न्यायालय इस कमी को सुधारने या उसे*

पूरा करने में अपनी सहायता नहीं कर सका। अदालतें तय करेंगी कि कानून क्या है और क्या होना चाहिए। अदालत निश्चित रूप से एक ऐसे निर्माण को अपनाती है जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को पूरा करेगा लेकिन खुद कानून नहीं बना सकता है। लेकिन विधायी निर्णय को नकारने के लिए न्यायिक सक्रियता का आह्वान करना संवैधानिक सद्भाव और साधनों की सौहार्दता को नष्ट करने वाला है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भारत संघ एवं अन्य बनाम प्राइजर लिमिटेड एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***2018 (2) एससीसी 39*** में दी गई है, जिसके पैराग्राफ संख्या 24 से 26 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं-

"24. *यदि धारा 26-ए के तहत शक्ति का प्रयोग अप्रासंगिक सामग्री के आधार पर या किसी भी सामग्री के आधार पर नहीं किया जाता है, तो धारा 26-ए द्वारा विचार की गई संतुष्टि ही नहीं होगी और इस आधार पर शक्ति का प्रयोग निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध बनाने के लिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में, शब्दों को संवैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।*

25. *सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम ट्राई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम ट्राई, (2016) 7 एससीसी 703] मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः (एस. सी. सी. पीपी. 740-41, पैरा 50-52)*

"50. लेकिन यह कहा गया कि उपरोक्त विनियमन को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि यह केवल तभी लागू होगा जब गलती

सेवा प्रदाता की हो। हमें डर है कि इस तरह का पाठ्यक्रम कानून में हमारे लिए खुला नहीं है, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि पढ़ने का सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब किसी क़ानून या विनियमन में उपयोग किए गए सामान्य शब्दों को एक विशेष तरीके से सीमित किया जा सकता है ताकि किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन न हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पढ़ने के सिद्धांत से संबंधित शुरुआती फैसलों में से एक में दिया गया था, अर्थात्, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 में संघीय न्यायालय का निर्णय, पुनः [हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937, पुनः 1941 एस. सी. सी. ऑनलाइन एफ. सी. 3: ए आई आर 1941 एफ. सी. 72]। उस फैसले में, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम की धारा 3 में "संपत्ति" शब्द को पढ़ा गया था ताकि कृषि भूमि को शामिल न किया जा सके, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों के बाहर होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि विधायिका का इरादा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने का नहीं था। "संपत्ति" शब्द को पढ़ते हुए, संघीय न्यायालय ने कहाः

'... यदि विधायिका की शक्ति के भीतर उद्देश्यों के लिए सामान्य शब्दों का प्रतिबंध किसी अधिनियम को कुछ भी नहीं या कुछ भी नहीं के साथ छोड़ना होगा, या किसी अधिनियम को उस अधिनियम से अलग, और केवल डिग्री में नहीं, जिसमें सामान्य

शब्दों को व्यापक अर्थ दिया गया था, तो यह स्पष्ट है कि समग्र रूप से अधिनियम को अमान्य माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में किसी भी विश्वास के साथ यह दावा करना असंभव है कि विधायिका ने सामान्य शब्दों का इरादा किया था. जिसका उपयोग केवल संकीर्ण अर्थों में किया गया है : एस. एस. कालिबिया के मालिक बनाम विल्सन (एस. एस. कालिबिया के मालिक बनाम विल्सन, (1910) 11 सी. एल. आर. 689 (ऑस्ट)], वैक्यूम ऑयल कंपनी प्रोप्राइटरी लिमिटेड *बनाम क्वींसलैंड [*वैक्यूम ऑयल कंपनी प्रोप्राइटरी लिमिटेड *बनाम क्वींसलैंड, (1934) 51 सी. एल. आर. 677 (ऑस्ट)], आर. वी. सुलह और मध्यस्थता का राष्ट्रमंडल न्यायालय, एक्स पी व्हायब्रो एंड कंपनी. (आर. वी. राष्ट्रमंडल सुलह और मध्यस्थता न्यायालय, एक्स पी व्हायब्रो एंड कंपनी, (1910) 11 सी. एल. आर. 1 (ऑस्ट)] और ब्रिटिश इंपीरियल ऑयल कंपनी लिमिटेड बनाम* संघीय कराधान आयुक्त *[ब्रिटिश इंपीरियल ऑयल कंपनी लिमिटेड बनाम* संघीय कराधान आयुक्त, *(1925) 35 सी. एल. आर. 422 (ऑस्ट)]।'*

51. इस फैसले के बाद डी. टी. सी. बनाम मजदूर कांग्रेस [डी. टी. सी. बनाम मजदूर कांग्रेस, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 600] मामले में इस अदालत की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। उस मामले में, यह सवाल उठा कि क्या कोई विशेष विनियमन जो किसी स्थायी और पुष्ट कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का नोटिस जारी करके उसकी सेवाओं

को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, या बिना कोई कारण बताए और कर्मचारी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस तरह के नोटिस के बदले में भुगतान करके, अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है। मामले की सुनवाई करने वाले चार विद्वान न्यायाधीशों, अकेले मुख्य न्यायाधीश ने इस पहलू पर असहमति जताते हुए निर्णय लिया कि विनियमन को पढ़ा नहीं जा सकता है, और इसलिए, इसे असंवैधानिक माना जाना चाहिए। सावंत, न्यायमूर्ति द्वारा इस पहलू पर दिए गए प्रमुख निर्णय में, इस न्यायालय ने कहाः

'255. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क़ानून को पढ़ने या फिर से बनाने का सिद्धांत सीमित परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। इसका उपयोग अनिवार्य रूप से, सबसे पहले, किसी क़ानून को उसकी असंवैधानिकता के कारण निरस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत का विस्तार है कि जब दो व्याख्याएं संभव हैं- एक इसे संवैधानिक बनाती है और दूसरी इसे असंवैधानिक बनाती है, तो पहली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह असंवैधानिकता या तो विधायिका की अक्षमता से उत्पन्न हो सकती है क्योंकि कानून बनाना या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना। दूसरी स्थिति जो इसकी सहायता को आमंत्रित करती है, वह है जहां क़ानून के प्रावधान अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं, और क़ानून के उद्देश्य से विधायिका के इरादों को इकट्ठा करना संभव है, जिस संदर्भ में प्रावधान होता है और जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया

गया है। हालाँकि, जब प्रावधान को एक निश्चित और असंदिग्ध भाषा में डाला जाता है और इसका इरादा स्पष्ट होता है, तो इसे सुधारने या मोड़ने की अनुमति नहीं है, भले ही ऐसा पुनर्कथन उचित कारण और विवेक के अनुरूप हो। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत के लिए क़ानून का पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है। इसका एकमात्र कर्तव्य है कि इसे निरस्त किया जाए और यदि वह चाहे तो इसे संशोधन करने के लिए विधायिका पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा, यदि अदालतों द्वारा क़ानून को फिर से बनाने से इसकी विकृति होती है तो उस मार्ग से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। उन स्थितियों में से एक जहां सिद्धांत को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, वह है जहां कानून में व्यापक परिवर्धन और विलोपन की आवश्यकता होती है। इस तरह की कवायद करना न केवल अदालत के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।'

52. आक्षेपित विनियमन के लिए उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि विनियमन की भाषा निश्चित और स्पष्ट है- प्रत्येक सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के भीतर होने वाले प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए कॉलिंग उपभोक्ता के खाते में एक रुपये का भुगतान करना होता है। उपरोक्त विनियमन के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन आगे यह स्पष्ट करता है, पैरा 19 में कि, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कॉल ड्रॉप सेवा प्रदाता की ओर से सेवा वितरण में कमी के उदाहरण हैं। इस

प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित विनियमन इस तथ्य पर आधारित है कि केवल सेवा प्रदाता की गलती है और उसे उस गलती के लिए भुगतान करना होगा। इन परिस्थितियों में, विनियमन में एक परंतुक को पढ़ना कि यह उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा जो स्वयं गलती पर है, सामान्य शब्दों को किसी विशेष अर्थ तक सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रावधान में कुछ जोड़ना है जो मौजूद नहीं है, जो स्वयं न्यायालय द्वारा कानून बनाने से कम नहीं होगा। इस कारण से, विद्वान महान्यायवादी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि विवादित विनियमन को उनके द्वारा सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाए।"

(मूल में जोर दिया गया है)

26. इसके अलावा, वैधानिक व्याख्या के मामले में, शब्दों को केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब धारा की शाब्दिक व्याख्या एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाए। जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया है, धारा 26-ए के शाब्दिक पठन पर निर्माण से ऐसा कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए धारा 26-ए को बचाने के लिए डॉ. सिंघवी के तर्क को शब्दों में पढ़ने के लिए खारिज किया जाना चाहिए।"

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) का उल्लेख किया है। जो इस प्रकार है:-

22. डिग्री प्रदान करने का अधिकारः-

(1) XXX XXX XXX

(II) XXX XXX XXX

(iii) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "डिग्री" का अर्थ है कोई भी ऐसी डिग्री जो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ हो, जिसे आयोग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।"

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिग्री शब्द को परिभाषित किया है, लेकिन उक्त परिभाषा "डिग्री" शब्द की परिभाषा को केवल "स्नातक डिग्री" या "स्नातक डिग्री" तक सीमित नहीं करती है। इस संबंध में, ***प्रोफेसर यशपाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (2005) 5 एस. सी. सी. में सूचित 420*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है अनुच्छेद संख्या 36 से 38 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया है:-

*"**36.** यू. जी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है- विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए एक अधिनियम। इस अधिनियम की धारा 2 (एफ) एक विश्वविद्यालय को परिभाषित करती है और इसका अर्थ है एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, और इसमें जैसी कोई भी संस्था शामिल है आयोग, संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से, इस अधिनियम के तहत इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त कर सकता है। धारा 12 में यह प्रावधान है कि आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा कि वह संबंधित विश्वविद्यालयों या अन्य निकायों के साथ परामर्श करके ऐसे सभी कदम उठाए जो वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के*

मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझे और अधिनियम के तहत अपने कार्यों के उद्देश्य से आयोग खंड (ए) से (जे) में उल्लिखित ऐसे सभी कार्य कर सकता है। धारा 22 और 23 महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"22. डिग्री प्रदान करने का अधिकार।- (1) डिग्री प्रदान करने या देने के अधिकार का प्रयोग केवल केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान या डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त संस्थान द्वारा किया जाएगा।*
>
> *(2) उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी उपाधि को प्रदान करने या प्रदान करने का हकदार नहीं होगा।*
>
> *(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'डिग्री' का अर्थ है कोई भी ऐसी डिग्री जो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, आयोग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती है।*
>
> *23. कुछ मामले में 'विश्वविद्यालय' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध - केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय के अलावा कोई भी संस्थान, चाहे वह निगमित निकाय हो या नहीं, किसी भी तरह से अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द को जोड़ने का हकदार नहीं होगाः*

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो साल की अवधि के लिए, उस संस्थान पर लागू नहीं होगी, जिसके नाम के साथ ऐसे प्रारंभ से तुरंत पहले 'विश्वविद्यालय' शब्द जुड़ा हुआ था।"

37. *यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 22 को ध्यान में रखते हुए, डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल एक विश्वविद्यालय या उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान या विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम द्वारा डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सशक्त संस्थान द्वारा किया जा सकता है। "डिग्री" क्या है और इसका क्या अर्थ है, यह यू. जी. सी. अधिनियम में नहीं दिया गया है, लेकिन शब्दकोशों और मानक पुस्तकों में दिए गए शब्द का अर्थ नीचे दिया गया हैः*

वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोशः

1. "एक कॉलेज, विश्वविद्यालय या पेशेवर स्कूल द्वारा छात्रों को एक निर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट वाले अध्ययन के एकीकृत कार्यक्रम के पूरा होने पर, कुछ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर और अक्सर एक शोध प्रबंध या अन्य स्वतंत्र शोध परियोजना के पूरा होने पर प्रदान की जाने वाली उपाधि।"

2. "अनुष्ठानिक क्रम या समाज प्रवीणता के एक चरण में प्राप्त सदस्यता का ग्रेड या वर्ग को दर्शाता है जो अक्सर एक निर्धारित परीक्षा या परीक्षा के बाद होता है।"

व्हार्टन का लॉ लेक्सिकॉनः

"एक व्यक्ति की स्थिति, एक बैरिस्टर-एट-लॉ होने के रूप में, या एक विश्वविद्यालय के कला स्नातक या स्नातकोत्तर होने के लिए।"

चैम्बर्स ट्रॅटिएथ सेंचुरी डिक्शनरीः

"विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त विशिष्टता का चिह्न, चाहे वह परीक्षा द्वारा अर्जित हो या सम्मान के चिह्न के रूप में दिया गया हो।"

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन (दूसरा संस्करण):

"किसी छात्र को किसी कला या विज्ञान में प्रवीणता के लिए प्रदान किया जाने वाला विशिष्ट चिह्न; निर्दिष्ट प्रवीणता का विश्वविद्यालय डिप्लोमा।"

एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना

"डिग्री"- एक कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि, जो दर्शाती है कि सीखने के क्षेत्र में एक निश्चित कदम या ग्रेड प्राप्त किया गया है। स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाले डिप्लोमा का पुरस्कार स्नातक अध्ययन के समापन को चिह्नित करता है। मास्टर और डॉक्टर की डिग्री स्नातक अध्ययन को पुरस्कृत करती है। अन्य डिग्री पेशेवर काम की तैयारी का प्रमाण हैं- उदाहरण के लिए एम. डी. (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)।

हालाँकि, 20वीं सदी में, अमेरिकी विश्वविद्यालयों और इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों (ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को छोड़कर) में बीए से आगे के अध्ययन और (आमतौर पर) थीसिस की प्रस्तुति के आधार पर एमए की डिग्री दी जाती है।

स्कॉटलैंड एक अपवाद है, जहाँ एम. ए. उनकी स्थापना के बाद से सभी छह विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली पहली डिग्री रही है। एमए से परे काम करने के लिए बैचलर ऑफ फिलॉसफी और बैचलर ऑफ लेटर्स की डिग्री दी जाती है।

द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका

"डिग्री"- शिक्षा में, शैक्षणिक उपलब्धि की सीमा को इंगित करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली कई उपाधियों में से कोई भी। 13 वीं शताब्दी से डिग्री का पदानुक्रम, एक बार मध्ययुगीन गिल्ड प्रणाली से मिलता-जुलता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में, शैक्षणिक डिग्री का आधुनिक वर्गीकरण आमतौर पर स्नातक (या स्नातक), मास्टर और डॉक्टर होता है। कुछ अपवादों के साथ, मध्यवर्ती डिग्री, महाद्वीपीय यूरोप के विश्वविद्यालयों में स्नातक और मास्टर जैसी मध्यवर्ती डिग्री को छोड़ दिया गया है।

38. *विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री इस तथ्य का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष उच्च स्तर के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और अध्ययन के उक्त विषय में अपनी प्रवीणता को प्रमाणित करते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। डॉक्टरेट डिग्री के मामले में, यह प्रमाणित करता है कि डिग्री धारक ने कुछ मूल शोध कार्य करके संबंधित विषय में उच्च स्तर का ज्ञान और अध्ययन प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय की डिग्री किसी व्यक्ति को स्नातक या स्नातकोत्तर जैसी स्थिति प्रदान करती है। जिन लोगों ने शोध कार्य किया है और पीएचडी, डी. लिट या डी. एस. सी. की डिग्री प्राप्त की है, वे अपने नाम से पहले "डॉक्टर" शब्द लिखने के हकदार हैं और शिक्षित और जानकार व्यक्तियों के रूप में समाज में कुछ मात्रा में सम्मान प्राप्त करने के हकदार हैं।*

इसके अलावा, विश्वविद्यालय की डिग्री रखने का प्रमुख लाभ रोजगार के मामले में है, जहां किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर या पेशेवर डिग्री जैसी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती है। यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं और डॉक्टर या वकील जैसे निजी पेशे में बने रहना चाहते हैं, चिकित्सा परिषद या बार काउंसिल के साथ पंजीकरण आवश्यक है, जिसके लिए उक्त निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा या कानून में डिग्री, जैसा भी मामला हो, आवश्यक है। इसलिए एक शैक्षणिक डिग्री उसके धारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है और उसके भविष्य को आकार देने में एक लंबा रास्ता तय करती है। समाज के हित के लिए यह भी आवश्यक है कि शैक्षणिक डिग्री धारक के पास उस विषय में आवश्यक प्रवीणता और विशेषज्ञता होनी चाहिए जिसे डिग्री प्रमाणित करती है।"

9. विद्वान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि जहां तक फार्मेसी के क्षेत्र का संबंध है, जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि फार्मेसी अधिनियम अपने आप में फार्मेसी के विषय में एक पूर्ण संहिता है। यह कहा गया है कि भारतीय फार्मेसी परिषद का गठन भारत में फार्मेसी की शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए सशक्त एक निकाय के रूप में किया गया है और फार्मेसी अधिनियम विशेष रूप से उन उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों को शामिल करता है जिनके लिए फार्मेसी अधिनियम में अधिनियमित किया गया। वास्तव में विधायिका ने क़ानून के तहत एक स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण, यानी भारतीय फार्मेसी' परिषद की स्थापना की है, इसलिए भारतीय फार्मेसी परिषद को फार्मेसी के क्षेत्र को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। इस संबंध में, माननीय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ. एस. के. तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और अन्य, ने ***(2021) 10 एससीसी 657*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। में रिपोर्ट किया। संदर्भ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 के लिए भी किया गया है, जो 16.07.2019 पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसके तहत और जिसके तहत इसे निम्नानुसार अधिसूचित किया गया हैः-

> *"केंद्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय फार्मेसी परिषद की सिफारिशों पर निर्णय लिया कि एक व्यक्ति के पास फार्मेसी है जो योग्यता उच्च योग्यता होने के कारण स्वचालित रूप से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगी जहां फार्मेसी में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र है।"*

10. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पुरी तरह से है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रवेश लेता है, फार्म डी पाठ्यक्रम में मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, फार्म डी विनियम, 2008 के अनुसार, पाठ्यक्रम की अवधि छह शैक्षणिक वर्ष है, जबकि फार्म डी (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति के मामले में, बी. फार्म पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद, पाठ्यक्रम की अवधि केवल तीन शैक्षणिक वर्ष है, इसलिए, विनियमन, 2008 में यह पूर्वधारणा की गई है कि छह वर्ष की अवधि के लिए फार्म.डी. पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के पास बी.फार्म. की योग्यता भी होनी चाहिए और इस कारण से, भारत सरकार ने दिनांक 16.07.2019 की अधिसूचना के तहत फार्म.डी. की योग्यता

रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न पदों के लिए पात्र बना दिया है, जहां फार्मेसी में डिप्लोमा या फार्मेसी में स्नातक या फार्मेसी में मास्टर योग्यता रखने वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र है।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी-आयोग ने दिनांकित 22.11.2022 के विज्ञापन के खंड 3 के तहत हिंदी में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते समय एक शरारत की है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में नियम, 1945 के नियम 49 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का संस्करण है। इस संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि विज्ञापन और वैधानिक नियमों में दिए गए प्रिस्क्रिप्शन में टकराव/भिन्नता के मामले में, और वैधानिक नियमों में, वैधानिक नियमों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ***कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2022) 11 एससीसी 392*** में दी गई है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-आयोग के दिनांक 05.04.2024 के आक्षेपित निर्णय द्वारा गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है और वास्तव में, वह ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह से रखता है।

12. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, अर्थात प्रत्यर्थी सं. 1 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 08.10.2014 की अधिसूचना के माध्यम से बिहार औषधि नियंत्रक संवर्ग विनियम, 2014 को अधिसूचित किया है और इसका खंड 5 औषधि निरीक्षक के मूल संवर्ग पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, जो नियम, 1945 के नियम 49 के अनुसार हो। नियम 1945 के नियम 49 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति वह होगा जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित

किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री होगी, जिसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता होगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ औषध विज्ञान या औषधि विज्ञान में एक डिग्री है, तथापि, याचिकाकर्ता औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने का मामला बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके फार्म डी की योग्यता रखने के आधार पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा 16.07.2019 पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना का आश्रय ले रहा है. फिर भी तथ्य यह है कि कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया है। जहाँ तक औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का संबंध है, नियम, 1945 के नियम 49 में। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान वकील का निवेदन है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास फार्मेसी में स्नातक की डिग्री नहीं है, इसलिए वह औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं है। ***सत्येंद्र सिंह एवं अन्य बनाम संजय कुमार एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की वरिष्ठतम खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें ***2001 (1) पीएलजेआर 104*** में रिपोर्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करने वाला नियम एक नीतिगत निर्णय है, इसलिए ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है, क्योंकि न्यायालय नीतिगत मामले पर एक अपीलीय मंच के रूप में नहीं बैठता है और यदि नियम किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो न्यायालय नियुक्ति प्राधिकारी को केवल तभी इस पर विचार करने का निर्देश दे सकता

है जब कोई दावा किया जाता है कि कुछ अन्य योग्यता निर्धारित योग्यता के बराबर है। हालाँकि, न्यायालय न तो ऐसी योग्यता जोड़ सकता है और न ही इसकी समानता निर्धारित कर सकता है और न ही हलफनामे और विशेषज्ञ की राय के आधार पर अंतिम निर्णय ले सकता है और इस मुद्दे पर निर्णय ले सकता है। इस संबंध में ***सत्येंद्र सिंह*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय के पैरा क्रमांक 12 से 15 को नीचे पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा।

> *"**12.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करना एक नीतिगत निर्णय है। सरकार तथ्यों और परिस्थितियों की संख्या, विशेषज्ञों की राय और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए एक नीति तैयार करती है। ऐसे मामलों में न्यायिक न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब अधिकारियों ने मनमाने ढंग से या वैधानिक या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। न्यायालय नीतिगत मामले पर एक अपीलीय मंच के रूप में नहीं बैठता है। इसके पास नीतिगत मामले को फिर से तैयार करने की कोई शक्ति नहीं है और यदि नीतिगत मामला के किसी भी कानूनी से पीड़ित पाया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है. कमजोरियों को निरस्त किया जाना है और मामले को निर्धारित कानून के अनुसार नीतिगत मामले पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को भेजा जाता है। यदि किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले नियम बनाए गए हैं, तो न्यायालय के पास नियमों को फिर से तैयार करने या साधारण कारण से अतिरिक्त योग्यता जोड़कर नियम को पूरक करने की कोई शक्ति नहीं है जो नियुक्ति प्राधिकरण का कार्य है और किसी भी कानूनी कमी के मामले में न्यायालय केवल नियुक्ति प्राधिकरण को विशेषज्ञ की राय और अन्य प्रासंगिक विचार के आधार पर मामले पर विचार*

करने का निर्देश दे सकता है। न्यायालय शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर भर्ती नियमों में योग्यता की समानता या जोड़ का निर्धारण नहीं कर सकता है।

13. *जे. रंगास्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार [(1990) 1 एससीसी 288] के मामले में, विचार के लिए प्रश्न रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी. ए. आर. सी.) से रेडियोलॉजिकल फिजिक्स (जैसा कि चिकित्सा में लागू होता है) में डिप्लोमा था और उसने दावा किया या कि उसकी योग्यता बेहतर योग्यता थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था। उक्त मामले पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं की प्रासंगिकता पर विचार करना या याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित ऐसी डॉक्टरेट और बीएआरसी डिप्लोमा की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करना और यह तय करना या निर्देश देना न्यायालय का काम नहीं है कि संबंधित पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा मामले में विचार करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए और उस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।*

14. *उड़ीसा सरकार बनाम हनीचल राय [(1998) 6 एस. सी. सी. 626] के मामले में, भर्ती नियमों ने राज्य सरकार को भर्ती नियमों के प्रावधानों में ढील देने की शक्ति निहित की। उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को छूट के मामले पर विचार करने का निर्देश देने के बजाय खुद ही कानून के प्रावधान में छूट दे दी। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि*

न्यायाधिकरण कानून के प्रावधानों में ढील के देने पर फैसला नहीं कर सकता है। नियम के अनुसार, राज्य सरकार नियमों में दी गई छूट पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थी और तदनुसार, आदेश को दरकिनार कर दिया और राज्य सरकार को छूट के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया।

15. *इस प्रकार कानून यह तय करता है कि जब भर्ती नियम एक आवश्यक योग्यता प्रदान करते हैं और यह सवाल उठता है कि क्या कोई अन्य योग्यता भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता के बराबर है या नहीं, तो उस प्रश्न का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और न्यायालय नियम में संशोधन या इसे फिर से तैयार नहीं कर सकता है और न्यायालय केवल संबंधित प्राधिकारी को विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के बाद विशेष रूप से इस तरह के तकनीकी मामले में मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दे सकता है। न्यायालय शपथ पत्र और विशेषज्ञ की राय के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकता है और ऐसे मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत सीमित है और मामले में यदि राज्य सरकार मामले का निर्णय लेती है और वह मनमाना, दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगा।"*

13. प्रतिवादी-आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित किशोर ने वर्तमान रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विज्ञापन संख्या 09/2022 के अनुसरण में आवेदन पत्र नहीं भरा था, हालांकि, उन्होंने आवेदन पत्र केवल 19.05.2023 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4751/2023 में अंतरिम आदेश पारित होने के बाद ही भरा है, जिसके कारण 23.05.2023 को महत्व नोटिस जारी किया

गया। फिर भी, उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.03.2024 के आदेश के माध्यम से वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है, इस प्रकार दिनांकित 19.05.2023 का अंतरिम आदेश अब जीवित नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने के लिए दिया गया लाभ अब समाप्त हो गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता का आवेदन अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को वैकल्पिक बना दिया गया है। फिर भी प्रतिवादी- आयोग के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जारी एक अन्य आदेश यह है कि दिनांक 19.05.2023 के अंतरिम आदेश द्वारा, आवेदकों को आवेदन भरने की स्वतंत्रता दी गई थी, हालांकि, इस शर्त के साथ कि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अंततः 2023 के सी. डब्ल्यू, जे. सी. सं. 4751 वाले उक्त रिट याचिकाकर्ता के परिणाम पर निर्भर करेगी, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त रिट याचिका अब वापस ले ली गई है और खारिज कर दी गई है।

14. प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वास्थ्य विभाग के निर्णय को चुनौती देने के अभाव में वर्तमान रिट याचिका के योग्य नहीं होने के संबंध में एक और मुद्दा उठाया है, जैसा कि सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 04.08.2023 में निहित है, जिसके तहत यह माना गया है कि फार्म डी (डॉक्टर ऑफ फार्मेसी) फार्मेसी शिक्षा में एक नई डिग्री है, जिसका उल्लेख औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए नियम, 1945 के नियम 49 में निर्धारित योग्यता में नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 04.08.2023 के उक्त आदेश से व्यथित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि नियम, 1945 का नियम 49 औषधि निरीक्षकों की योग्यता निर्धारित करता है और प्रतिवादी-आयोग द्वारा 2022 के विज्ञापन संख्या 9 में निर्धारित योग्यता न केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा

भेजी गई मांग के अनुरूप है, बल्कि प्रावधानों के अनुसार भी है नियम 1945 के नियम 49 में निहित। केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2023 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4751 में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजा था, जिसमें 16 जुलाई 2019 की भारतीय राजपत्र अधिसूचना के आलोक में निर्धारित योग्यता के साथ फार्म डी शैक्षणिक योग्यता की समानता पर विचार करने के मुद्दे पर पूरी तरह से विचार करने का अनुरोध किया गया था. जिसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 04.08.2023 के पत्र के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की, बहुत स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि फार्म डी (डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी) फार्मेसी शिक्षा में एक नई डिग्री है, जिसका उल्लेख नियम, 1945 के नियम 49 में निर्धारित योग्यता में नहीं किया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए और नियम 1945 के नियम 49 में नए पाठ्यक्रम/डिग्री को शामिल करने के लिए, उक्त नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है, हालांकि, नियम 1945 में आवश्यक संशोधन के अभाव में, पात्रता मानदंड, जैसा कि 2022 के विज्ञापन सं. 09 में प्रकाशित किया गया है, नियम, 1945 के नियम 49 के अनुरूप है।

15. प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अगला तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता उच्च डिग्री अर्थात डॉक्टरेट की डिग्री धारण कर रहा है जबकि ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता फार्मेसी में डिग्री है, हालांकि, तथ्य यह है कि यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि डॉक्टरेट की डिग्री फार्मेसी में डिग्री के बराबर है। प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ***महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वाराडे और अन्य 2019 (6) एस. सी. सी. 362*** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

पर भरोसा किया है भले यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का निर्णय करना नियोक्ता का काम है और पात्रता की शर्तों को निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है, विज्ञापन के व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा आवश्यक योग्यता के बराबर वांछनीय योग्यता के संबंध में मुद्दे पर बहुत कम विचार करें। तुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। इस संबंध में, अनुच्छेद सं. 19 ***संदीप श्रीराम वाराडे और अन्य*** (ऊपर) के मामले में दिए गए पूर्व-कथित निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

> *"**9.** किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएँ नियोक्ता को तय करनी होती हैं। नियोक्ता वरीयता के किसी भी अनुदान सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यता निर्धारित कर सकता है। यह वह नियोक्ता है जो नियोक्ता की जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार एक उम्मीदवार की आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अदालत पात्रता की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती है, विज्ञापन के व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा आवश्यक योग्यता के बराबर वांछनीय योग्यताओं के संबंध में इस मुद्दे पर बहुत कम विचार कर सकती है। तुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो अदालत उसी पर निर्णय नहीं दे सकती है। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या यह किसी भी नियम या कानून के विपरीत है तो मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उचित आदेशों के बाद नियुक्ति प्राधिकरण के पास वापस जाना होगा। किसी भी मामले में अदालत, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है, यह तय करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की अध्यक्षता में नहीं बैठ सकती है और विज्ञापन की शर्तों की व्याख्या उसी की साधारण भाषा के विपरीत नहीं कर सकती है।"*

16. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2021) 16 एससीसी 340*** में दी गई है, पैराग्राफ संख्या 29 और 30 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: —

> ***"29.*** *इसके बाद, न्यायालय ने पी.एम. लता [पी.एम. लता बनाम केरल राज्य, (2003) 3 एस.सी.सी. 541], ज्योति के.के. [ज्योति के.के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस.सी.सी. 596] और अनीता [पंजाब राज्य बनाम अनीता, (2015) 2 एस.सी.सी. 170] में दिए गए पिछले फैसलों पर चर्चा की, फिर निष्कर्ष निकाला कि डिप्लोमा धारकों की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और निम्नानुसार माना गया:*
>
> > *"26. ज्योति के. के. मामले में फैसले पर जो व्याख्या की गई है, हम उससे सहमत हैं [ज्योति के. के. बनाम. केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस. सी. सी. 596] अनीता [पंजाब राज्य बनाम अनीता, (2015) 2 एस. सी. सी. 170] में बाद के निर्णय में। ज्योति के. के. में निर्णय [ज्योति के. के. बनाम. केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस. सी. सी. 596] ने नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को लागू कर दिया। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाती है, भले ही वह कम हो। किसी पद के लिए योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता*

निर्धारित करने का हकदार है। यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करना राज्य के लिए, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, एक मामला है। ज्योति के. के. में निर्णय [ज्योति के. के. बनाम. केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस. सी. सी. 596] एक विशिष्ट वैधानिक नियम को लागू किया गया जिसके तहत एक उच्च योग्यता रखने के लिए कम योग्यता के अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान मामले में इस तरह के नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, खंड पीठ [2017 की इम्तियाज अहमद बनाम जहूर अहमद राधर एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.) संख्या 135, ने उच्च न्यायालय के 12-10-2017 (जे. एंड के.) पर निर्णय लिया, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले [जहूर अहमद राथर बनाम जे. एंड के. राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 936] को उलटने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अपीलकर्ता निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे। हम खंड पीठ के निर्णय [2017 के इम्तियाज अहमद बनाम जहूर अहमद राथर एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.) संख्या 135 में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के

लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की आवश्यकताएँ, यह एक साधारण कानून है, जो प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य उन सामाजिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रख सकता है जिनके लिए सामाजिक संरचना में नौकरी के अवसरों के सृजन की आवश्यकता होती है। ये सभी अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं। न्यायिक समीक्षा को सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। यही कारण है कि ज्योति के. के. में निर्णय लिया गया (ज्योति के. के. बनाम, केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस. सी. सी. 596] को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत एक उच्च योग्यता का धारण, जो कम योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है, इस पद के लिए पर्याप्त माना जाता था। यह विशिष्ट नियम के संदर्भ में था कि ज्योति के. के. में निर्णय (ज्योति के. के. बनाम. केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एस. सी. सी. 596] बदल गया।"

30. पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनित कुमार दास [पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनित कुमार दास, (2021) 12 एस. सी. सी. 80] मामले में इस अदालत के बाद के फैसले पर ध्यान देना भी उपयोगी होगा, जहां यह मुद्दा था कि क्या अपीलकर्ता बैंक में चपरासी के पद के लिए, एक डिग्री धारक (स्नातक) की नियुक्ति की जा सकती है, नियोक्ता के सचेत निर्णय को देखते हुए, कि केवल उन लोगों पर विचार किया जाएगा जिनके पास 10+2 उत्तीर्ण योग्यता है और

स्नातक योग्यता वाले लोगों पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति, जो एक स्नातक था, इस तथ्य को दबाने के बाद कि उसके पास एक डिग्री थी, और इसका खुलासा नहीं किया, असमर्थनीय था। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि किस श्रेणी के पदों पर कौन सी योग्यताएं लागू होती हैं, यह नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार का विषय है, जिस पर अदालतें हस्तक्षेप करने में देरी करेंगी। यह निर्णय भी वर्तमान मामले में निष्कर्षों का समर्थन करता है, क्योंकि नियोक्ता, एच. पी. एस. ई. बी. का कहना है कि वह डिग्री पर विचार करता है- जे. ई. के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र धारक।

17. इस प्रकार, प्रत्यर्थी-आयोग के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह निवेदन है कि यदि नियम किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हैं, यदि उसके पास वह नहीं है, लेकिन उच्च योग्यता है, तो निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार को विचाराधीन पद पर नियुक्त होने से वंचित कर देगा। नतीजतन, वर्तमान मामले में, चूंकि नियम, 1945 और 2022 का विज्ञापन सं. 09 भी कानून द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री के लिए औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, इसलिए वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की तरह उच्च योग्यता रखने वाला व्यक्ति, जिसकी योग्यता फार्मा डी है, यानी फार्मेसी में डॉक्टरेट, औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा। इसलिए, प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका अयोग्य है और खारिज किए जाने के योग्य है।

18. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील को भी सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

19. विचाराधीन मुद्दा एक संकीर्ण दायरे में निहित है, क्योंकि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर "अयोग्य उम्मीदवार" की श्रेणी में रखा गया है कि उसके पास दवा निरीक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं है, यानी कानून द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री, बल्कि उसके पास उच्च योग्यता है, यानी फार्म डी (फार्मेसी में डॉक्टरेट)। इस प्रकार यह निर्णय लिया जाना है कि क्या उच्च योग्यता रखने से पहले कम योग्यता का अधिग्रहण माना जाता है, जो औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता का कारण बनता है।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विस्तार से कहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता केवल फार्मेसी में स्नातक की डिग्री तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि नियम, 1945 के नियम 49 में केवल यह निर्धारित किया गया है कि फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज या मेडिसिन में डिग्री रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रोफेसर ***यशपाल एवं अन्य*** (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है यह तर्क देते हुए कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री इस तथ्य का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष उच्च स्तर के पाठ्यक्रम का अध्यय किया है और अध्ययन के उक्त विषय में अपनी प्रवीणता को प्रमाणित करने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है और जहां तक डॉक्टरेट की डिग्री का संबंध है, यह प्रमाणित करता है कि

डिग्री धारक ने कुछ मूल शोध करके संबंधित विषय में उच्च स्तर का ज्ञान और अध्ययन प्राप्त किया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं की व्याख्या कि नियम, 1945 के नियम 49 में "फार्मेसी में डिग्री" के रूप में निर्धारित योग्यता को केवल स्नातक डिग्री या स्नातक डिग्री तक सीमित करती है, उत्तरदाताओं द्वारा "फार्मेसी में डिग्री" अभिव्यक्ति से पहले स्नातक या स्नातक को जोड़ने के बराबर है, जो ***नमित शर्मा*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शब्दों के जोड़ या घटाव से बचा जान चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 16.07.2019 की अधिसूचना पर भी भरोसा किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि फार्म डी योग्यता रखने वाला व्यक्ति उच्च योग्यता होने के कारण स्वचालित रूप से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा, जहां फार्मेसी में डिप्लोमा या फार्मेसी में स्नातक या फार्मेसी में मास्टर योग्यता रखने वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास पूरी तरह से शैक्षिक योग्यता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है।

21. यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बिहार सरकार द्वारा बनाए गए संवर्ग विनियम, 2014 के माध्यम, अधिसूचना दिनांक 08.10.2014, विनियम 2 (12) के माध्यम से, जिसमें औषधि निरीक्षक को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार औषधि नियंत्रक के संवर्ग के मूल संवर्ग पद पर नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि इसका विनियम 5 यह निर्धारित करता है कि औषधि निरीक्षक के मूल संवर्ग पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नियम, 1945 के नियम 49 और नियम, 1945 के नियम 49 के अनुसार होगी कि फार्मेसी या

फार्मास्युटिकल साइंसेज या मेडिसिन में डिग्री रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, दवा निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए नियम, 1945 के नियम 49 में या संवर्ग विनियम, 2014 के विनियम 5 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज या भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा। वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***प्रोफेसर यशपाल और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए एक फैसले में भी "डिग्री" और "डॉक्टरेट की डिग्री" के बीच अंतर किया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम, 1945 के नियम 49 और संवर्ग विनियम, 2014 के विनियमन 5 के संदर्भ में, औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता "डिग्री" है न कि "डॉक्टरेट की डिग्री"। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस आशय का उपरोक्त तर्क प्रस्तुत किया गया है कि औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता केवल फार्मेसी में स्नातक की डिग्री तक ही सीमित नहीं है, गलत है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

22. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि एक व्यक्ति के पास फार्म. डी योग्यता उच्च योग्यता होने के कारण स्वचालित रूप से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगी जहां फार्मेसी में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र है, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 ने न तो वैधानिक नियमों में संशोधन किया है, यानी ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 और न ही संवर्ग विनियम, 2014, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है, इसलिए, औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए आवश्यक

शैक्षिक योग्यता के बारे में वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का पालन करना आवश्यक है, जिसके पास निर्विवाद रूप से नैदानिक फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा में डिग्री है, इस प्रकार, इस स्कोर के साथ-साथ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क किसी भी विचार के योग्य नहीं है।

23. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र अन्य मुद्दा यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास फार्म डी योग्यता है, एक उच्च योग्यता होने के कारण, इसका मतलब यह होगा कि उसके पास कम योग्यता भी है, इसलिए वह निश्चित रूप से ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जिसके लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नैदानिक फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज या मेडिसिन में डिग्री है। जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के उक्त तर्क का संबंध है, इस न्यायालय ने पाया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि यह निष्कर्ष निकालना अनुमत नहीं है कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से उक्त प्रभाव के लिए किसी भी नियम के अभाव में, कम योग्यता के बावजूद, दूसरे के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है। किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण भर्ती नीति का विषय है और नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। इस प्रकार, यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इस संबंध में ***पुनीत शर्मा और अन्य*** (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए। वास्तव में, इस मामले के इस पहलू पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा जारी दिनांक 04.08.2023 के आदेश द्वारा भी संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फार्म-डी (डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी) फार्मेसी शिक्षा

में एक नई डिग्री है, जिसका उल्लेख नियम, 1945 के नियम 49 में निर्धारित योग्यता में नहीं है और नियम, 1945 के नियम 49 में नए पाठ्यक्रम/डिग्री को शामिल करने के लिए, जो ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, उक्त नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है, और नियम, 1945 में आवश्यक संशोधन के अभाव में। 2022 के विज्ञापन सं. 09 में प्रकाशित पात्रता मानदंड, नियम, 1945 के नियम 49 के अनुरूप है। इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 04.08.2023 के उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है, इस प्रकार, इस आधार पर भी, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इस समय, यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम अनित कुमार दास*** के मामले में विचाराधीन मुद्दे पर दिए गए एक अन्य निर्णय का संदर्भ देना उचित समझेगा, जिसकी रिपोर्ट ***(2021) 12 एससीसी 80*** में दी गई है, जिसके पैराग्राफ संख्या 17 से 17.3 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"**17.** वैसे भी, पात्रता मानदंड/शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना कि एक स्नातक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, बैंक द्वारा लिया गया एक सचेत निर्णय था और यह 2008 के परिपत्र पत्र संख्या 25 दिनांक 6-11-2008 के अनुसार था। जे. रंगा स्वामी [जे. रंगा स्वामी बनाम ए. पी. राज्य, (1990) 1 एस. सी. सी. 288] में, इस न्यायालय द्वारा यह माना और अभिनिर्धारित किया गया है कि विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं की प्रासंगिकता पर विचार करना न्यायालय का काम नहीं है।*
>
> ***17.1.** योगेश कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2003) 3 एस. सी. सी. 548] के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह माना और अभिनिर्धारित किया गया है कि लोक सेवा में भर्ती विज्ञापन की शर्तों और भर्ती नियमों,*

यदि कोई हो, के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। नियमों से विचलन अयोग्य व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देता है और कई अन्य "को वंचित करता है जो पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।

17.2. *जहूर अहमद राथर [जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद, (2019) 2 एस. सी. सी. 404] मामले में इस अदालत के हालिया फैसले में, इस न्यायालय ने ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग [(2010) 15 एस. सी. सी. 596] में इस न्यायालय के एक और निर्णय को अलग किया है यह विचार रखते हुए कि ऐसे मामले में जहां निम्न योग्यता निर्धारित की गई है, यदि किसी व्यक्ति ने उच्च योग्यता प्राप्त की है, तो ऐसी योग्यता को निश्चित रूप से पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है।* उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम अनीता [(2015) 2 एससीसी 170] में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी संज्ञान लिया, जिसमें इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर ज्योति के.के. के निर्णय में अंतर किया। ज्योति के.के. के निर्णय में अंतर करते हुए, पैरा 25 और 26 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

> *"25. ज्योति के. के. मामले में निर्णय पर पंजाब राज्य बनाम अनीता [(2015) 2 एस. सी. सी. 170] में दो विद्वान न्यायाधीशों के फैसले में विचार किया गया है। उस मामले में, जे, बी. टी./ई. टी. टी. योग्य शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नियमों के तहत, जे. बी. टी. शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता में जे. बी. टी. प्रशिक्षण में दो साल के पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक और मैट्रिक मानक या इसके समकक्ष पंजाबी और हिंदी का ज्ञान शामिल था। इस अदालत ने कहा कि किसी भी प्रतिवादी के पास निर्धारित योग्यता नहीं है और एमए,*

एमएससी या एमकॉम को "उच्च योग्यता" के रूप में नहीं माना जा सकता है। ज्योति के. के. में निर्णय को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने नोट किया कि उस मामले में नियम 10 (ए) (ii) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि उच्च योग्यता का अधिकार पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगा सकता है। इस तरह की शर्त के अभाव में, यह माना गया कि ऐसी परिकल्पना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता हैः

> *'15. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर यह दावा किया जाना चाहिए कि चूंकि निजी उत्तरदाताओं के पास उच्च योग्यता है, इसलिए जे. बी. टी./ई. टी. टी. की योग्यता, उन्हें जे. बी. टी./ई. टी. टी. शिक्षकों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाला माना जाना चाहिए। निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ज्योति के. के. मामले में उपरोक्त टिप्पणियों को दर्ज करते समय इस न्यायालय द्वारा जिन वैधानिक नियमों पर विचार किया गया था, उन्होंने उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति दी थी। निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णय में वैधानिक नियम को नीचे निकाला गया हैः*
>
> *"6. नियम 10 (ए) (ii) इस प्रकार हैः*
>
> ***10. (ए)(ii)*** इन नियमों या विशेष नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताएं विशेष नियमों में किसी पद के

लिए निर्दिष्ट योग्यता के समतुल्य हैं और ऐसी उच्च योग्यताएं जो उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्वधारणा बनाती हैं, वे भी उस पद के लिए पर्याप्त होंगी।"

नियम के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्च योग्यता रखने वाले पदों के लिए निर्धारित निम्न योग्यता का अधिग्रहण करना आवश्यक होगा। जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति को अधिकृत करने वाला ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

26. हम उस व्याख्या के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं जो अनीता में बाद के निर्णय में ज्योति के. के. में निर्णय पर रखी गई है। ज्योति के. के. में निर्णय ने नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को बदल दिया। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाती है, भले ही वह कम हो। किसी पद के लिए योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह, योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य को, भर्ती प्राधिकरण के

रूप में, निर्धारित करना है। ज्योति के. के. में निर्णय ने एक विशिष्ट वैधानिक नियम को चालू कर दिया जिसके तहत उच्च योग्यता रखने के लिए कम योग्यता के अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान मामले में ऐसा नियम अंतिम परिणाम में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, खंड पीठ [2017 की इम्तियाज अहमद बनाम जहूर अहमद राधर एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.) संख्या 135, ने उच्च न्यायालय के 12-10-2017 (जे. एंड के.) पर निर्णय लिया, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले [जहूर अहमद राधर बनाम जे. एंड के. राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 936] को उलटने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अपीलकर्ता निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे। हम खंड पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।"

(मूल में जोर)

इसके बाद इसे पैरा 27 में निम्नानुसार देखा गया हैः

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की आवश्यकताएँ, यह एक साधारण कानून है, जो प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक

नियोक्ता के रूप में राज्य सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए सामाजिक संरचना में रोजगार के रोजगार के सृजन की आवश्यकता होती है। ये सभी अनिवार्य रूप से नीति के मामले हैं। न्यायिक समीक्षा को सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। इसीलिए ज्योति के.के. मामले में लिए गए निर्णय को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्ति को पद के लिए पर्याप्त माना जाता था, जिसमें निम्न योग्यता प्राप्त करना भी शामिल था। ज्योति के.के. मामले में लिया गया निर्णय विशिष्ट नियम के संदर्भ में था।"

17.3. *इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, यह नियोक्ता पर है कि वह किसी भी पद के लिए योग्यता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारण और निर्णय करे और यह अदालतों पर विचार और मूल्यांकन करने के लिए नहीं है। अदालतों द्वारा नियोक्ता को किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए अधिक अक्षांश की अनुमति दी जाती है। इसके पीछे एक तर्क है। योग्यताएं किसी संस्थान या उद्योग या प्रतिष्ठान की आवश्यकता और हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। अदालतें योग्यताओं के इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन की समीचीनता या सलाह या उपयोगिता का आकलन करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं हैं। हालांकि, साथ ही, नियोक्ता पदों के लिए योग्यता निर्धारित करने में मनमाने ढंग से या काल्पनिक रूप से कार्य नहीं कर सकता है।*

वर्तमान मामले में, पात्रता मानदंड/शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना कि एक स्नातक उम्मीदवार पात्र नहीं होगा और उम्मीदवार को 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उचित है और जैसा कि ऊपर देखा गया है. यह बैंक द्वारा लिया गया एक सचेत निर्णय है जो 2008 से लागू है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता को अनुमति देने का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से गलती की है। चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हालांकि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षिक योग्यता के अनुसार पात्र नहीं थे।"

24. यह समान रूप से एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सार्वजनिक सेवा में भर्ती विज्ञापन की शर्तों और भर्ती नियमों के अनुसार सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि नियमों से विचलन से अनाम व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति मिलती है और कई अन्य लोग वंचित हो जाते हैं जो पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एनसीटी, दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट (2003) 3 एससीसी 548 में दी गई है।

25. अब वर्तमान मामले पर वापस आते हैं, नियम, 1945 के नियम 49, कैडर विनियम, 2014 के विनियम 5 और विज्ञापन संख्या 09, 2022 के खंड (3) से यह स्पष्ट है कि औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज या मेडिसिन में डिग्री के साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता है, इस प्रकार याचिकाकर्ता, जिसके पास उक्त योग्यता नहीं है और इसके बजाय उसने बी.फार्मा डिग्री प्राप्त किए बिना सीधे फार्म डी (डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी) की डिग्री प्राप्त

की है, औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र है, खासकर तब जब न तो नियम, 1945 और न ही कैडर विनियम, 2014 में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अनुसार उच्च योग्यता रखने से निम्न योग्यता प्राप्त करना पूर्व-मान्य हो।

26. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका में योग्यता नहीं है, इसलिए यह खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायाधीश)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।